बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 29 जुलाई, 1983।

पृष्ठ

विषय-सूची

अष्टम् बिहार विधान-सभा के नवम् सत्र के अनागत तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों का सभा-पटल पर रखा जाना।

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 21, 161, 231, 232	2-11
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 82, 484, 485, 486, 487,488	12—24
परिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	25—58
परिशिष्ट 2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	59-109
दैनिक निबंध	111—112

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों के अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय निरीक्षणों से इस बात की सम्पुष्टि हुई है कि क्षेत्र की कुछ जगहों में निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में निर्धारित दर से कम भुगतान होने की शिकायत मिली है जिसपर कारंवाई की जा रही है।

(2) सरकार खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। जब भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच कर सम्बन्धित मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने का प्रयास किया जाता है तथा प्रयास विफल होने पर दोषी नियोजकों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारंवाई की जाती है। प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1982 में बखरी प्रखण्ड में 152 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण के क्रम में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान के 40 मामले पाये गये। कम मजदूरी भुगतान के कारण बकाये मजदूरी की वसूली के लिए 35 दावा-पत्र विभिन्न न्यायालयों में दोषी नियोजकों के विरुद्ध दायर किये गये हैं जिसमें से 5 का निष्पादन श्रमिकों के पक्ष में हुआ है। इनसे सम्बन्धित श्रमिकों को 600.50 रुपया का लाभ हुआ।

विद्यालय का राष्ट्रीयकरण।

क्र-31. श्री राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रांची स्थित सती मंदिर पथ, पहाड़ी टोला में प्रभूलाल बाल शिक्षा निकेतन मध्य विद्यालय 1966 से चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा अधीक्षक, राँची, उपाधीक्षक, अवर विद्यालय निरीक्षक एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त विद्यालय का निरीक्षण कर अस्वीकृति वर्ष 1980 में प्रदान की जा चुकी है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 530 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं जिसमें अधिकांश आदिवासी हैं;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का सरकारीकरण करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(1) प्राप्त सूचना के आधार पर वह विद्यालय 1973 से चल रहा है न कि 1966 से।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) जिला राजकीयकरण समिति ने इस विद्यालय को राजकीयकरण करने का प्रस्ताव पास नहीं किया है। प्रस्ताव आने पर विचार किया जायगा।

पुल का निर्माण।

पथ-4. श्री सूर्यदेव राय—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बथनाहा प्रखण्ड में हरिवेला से सिरसिया गांव तक जाने वाली सड़क का निर्माण विधायक कोटा से हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में पुल का निर्माण नहीं होने से उक्त सड़क की उपयोगिता समाप्त हो जाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जनहित में क्या सरकार उक्त सड़क में पुल का निर्माण कराना चाहती है, यदि 'हां' तो कबतक 'नहीं' तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) प्रश्नाधीन पथ में अधवारा ग्रुप की एक नदी तथा दो नाले पड़ते हैं। तीनों स्थानों पर लकड़ी पुल के निर्माण पर क्रमशः 5.00 लाख, 3.60 लाख तथा 2.50 लाख अर्थात् कुल 11.10 लाख रुपया की लागत आयेगी। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आलोक में कार्य कराया जायेगा।